(c) Indian Cancer Research Centre, Bombay candidate vaccine has recently been put on field trial with effect from 30th January, 1987. Decision on introduction of leprosy vaccine as a total for prophylaxis under the National Leprosy Eradication Programme will be taken only after its efficacy is proved.

(d) Does not arise.

विभागेतर कर्मचारियों की कार्य दशायें

1816. **श्री राम चन्द्र विकल :** क्या **संचार** मंत्री 25 फरवरी, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 207 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संचार मंत्रालय में कार्य करने वाले विभागेतर कर्मचारियों की स्थिति बन्धुआ मजदूरों की स्थिति से भी बदतर है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सवूर समिति ने, जिसने इस समस्या की जांच की थी, अपना प्रतिवेदन दे दिया था, परन्तु इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संन्तोष मोहन देव) : (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को सरकार बंधुआ मजदूर नहीं मानती क्योंकि वे बंधुआ मजदूरों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते और उनके ऊपर डाकतार अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण एवं सेवा) नियम, 1964 के अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हैं ।

(ख) और (ग) सरकार इनकी सेवा शर्तों में सुधार की दृष्टि से समय-समय पर कार्रवाई करती रही है । सरकार द्वारा की गई नवीनतम कार्रवाई यह है कि श्री आर० आर० सवूर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय अतिरिक्त विभागीय समिति की नियुक्ति की गई है । इस समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं तथा वे सरकार के विचाराधीन है ।

Warning Notes of Pain Killers

1817. SHRI VIRENDRA VERMA:
SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the answer to Starred Question 105 given in the Rajya Sabha on the 4th March, 1987 asd state:

(a) whether Government are aware that the companies manufacturing pain killers are not inserting the 'warning note' and other precautions with the drug;

(b) if so, what action has been taken by Government so far to ensure the implementation of the directive by the Drug Controller of India stating the reasons for failure to check the non-implementation of the directive by the drug manufacturers; and

(c) what measures are contemplated by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) A recent survey carried out by the Government shows that some of the manufacturers of Dextropropoxyphene have failed to comply with the directives regarding insertion of warning notes and precautionery statements in the package inserts.

(b) and (c) To ensure that all formulations of Dextropropoxyphene bear warning notes and precautionary statements, the Drug Controller (India) has reiterated the necessary directives to the State Drug Controllers in January, 1987. The defaulting manufacturers of dextropropoxyphene formulations have also been directed to comply with the instructions in this regard.